3. **Form and manner of application for declaring an individual as a fugitive economic offender.**—(1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index containing the following materials, namely:-

(i) a copy of a warrant of arrest in relation to prosecution of a Scheduled Offence against the individual believed to be a fugitive economic offender issued by any Court in India;

(ii) a statement of reasons to believe that an individual is a fugitive economic offender;

(iii) a statement on any information available as to the whereabouts of the individual believed to be a fugitive economic offender;

(iv) any proof of effort undertaken to bring the individual believed to be a fugitive economic offender back to India;

(v) a list of properties or value of such properties believed to be the proceeds of crime, including any such property outside India for which confiscation is sought;

(vi) a list of properties or benami property owned by the individual believed to be a fugitive economic offender in India or abroad for which confiscation is sought;

(vii) a copy of a confiscation order issued by the Adjudicating Authority under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, if any;

(viii) a list of persons who may have an interest in any of the properties listed under clauses (v) and (vi).

(2) The index and material prepared under sub-rule (1) shall be signed on each page and forwarded to the Special Court in a sealed envelope, indicating a reference number and date of despatch.

(3) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register and dak register and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the application along with the materials are forwarded to the Special Court.

[F.No. 6/3/2017-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 806(अ)--केंद्रीय सरकार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 12 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भगोड़ा आर्थिक अपराधी (विशेष न्यायालयों के आदेश की सूचना की तामील और उसके निष्पादन के लिए संविदाकारी राज्यों को अनुरोध पत्र भेजने की प्रक्रिया) नियम, 2018 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी (संविदाकारी राज्यों को अनुरोध पत्र भेजने की प्रक्रिया) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) “प्राधिकृत अधिकारी” से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो उप निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ख) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं ;

(ग) “अधिनियम” से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17)अभिप्रेत है ।

(2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका उक्त अधिनियम में है ।

3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी पर विदेश में विशेष न्यायालय की सूचना की अनुरोध पत्र के माध्यम से तामील की प्रक्रिया--

(1) जहां अधिनियम की धारा 4 के अधीन आवेदन सम्यक् रूप से दाखिल किया जा चुका है, विशेष न्यायालय किसी व्यष्टि को जिस पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने का आरोप है, सूचना जारी करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय की सूचना की तामील, अनुरोध पत्र के माध्यम से की जाएगी ।

(3) अनुरोध पत्र इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप में होगा ।

(4) अनुरोध पत्र को अंतिम रूप दिए जाते समय, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 36 के अधीन स्थापित प्रवर्तन निदेशालय सभी विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्राधिकृत अधिकारी गृह मंत्रालय को अनुरोध पत्र तीन प्रतियों में अग्रेषित करेगा ।

(6) गृह मंत्रालय का नोडल अधिकारी संविदाकारी राज्य को अनुरोध पत्र का समय पर पारेषण सुनिश्चित करेगा ।

(7) अनुरोध पत्र विशेष न्यायालय की सूचना के साथ संविदाकारी राज्य में तामील को प्रभावी करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा ।

(8) अधिनियम की धारा 10 के अधीन किसी ढंग में सूचना की तामील, विशेष न्यायालय द्वारा प्रभावी तामील के रूप में मानी जाएगी ।

4. विशेष न्यायालय के आदेश के संविदाकारी राज्य में निष्पादन के लिए न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया—

(1) विशेष न्यायालय के आदेश के निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र इन नियमों से संलग्न प्ररूप में होगा ।

(2) विशेष न्यायालय द्वारा, उसके आदेश के संविदाकारी राज्य में निष्पादन के लिए न्यायालय या संबद्ध प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी करने के पश्चात्, प्राधिकृत अधिकारी उसे तीन प्रतियों में गृह मंत्रालय को अग्रेषित करेगा ।

(3) गृह मंत्रालय का नोडल अधिकारी संविदाकारी राज्य को अनुरोध पत्र का समय पर पारेषण सुनिश्चित करेगा ।

प्ररूप

[नियम 3 का उपनियम (3) और नियम 4 का उपनियम (1) देखें]

अनुरोध पत्र का प्ररूप

1. अनुसूचित अपराध/संक्षिप्त तथ्यों के ब्यौरे

2. विधि की लागू धाराओं का संदर्भ (ब्यौरा आवश्यक नहीं)

3. जांच से उत्पन्न होने वाले कारणों का संक्षिप्त संदर्भ जो यह उपदर्शित करता है कि अनुरोधित भगोड़ा आर्थिक अपराधी संविदाकारी राज्य में उपस्थित है और संविदाकारी राज्य में भगोड़े आर्थिक अपराधी का अपराध से आगम या संपत्ति अवस्थित हैं ।

4. संविदाकारी राज्य से चाही गई सहायता के संक्षिप्त ब्यौरे, अर्थात् विशेष न्यायालय के आदेश की सूचना की तामील और निष्पादन ।

5. अनुरोध भेजने का आधार, अर्थात् भारत और संविदाकारी राज्य के मध्य आपराधिक मामलों में आपसी विधिक सहायता संधि/कोई अन्य अभिसमय या संधि (ऐसे अभिसमय/संधि का शीर्ष दिया जाना चाहिए के उपबंध/या व्यतिकारी आश्वासन के आधार पर)

अनुरोध पत्र के ब्यौरे

1. देश का सही शासकीय नाम
2. संपर्क सूचना/संपर्क अधिकारी
3. या तो संधि या करार का सही उल्लेख (एमएलएटी देश)
4. व्यतिकारी आश्वासन/व्यतिकारी वचनबंध (गैर-एमएलएटी देश)
5. राजभाषा में प्रमाणित अनुवाद
6. अनुरोध पत्र संविदाकारी राज्य के सही केंद्रीय प्राधिकारी या न्यायालय को संबोधित किया जाना चाहिए।
7. यदि किसी संविदाकारी राज्य की अन्य अपेक्षाएं और रूपविधान है, जिसका अनुरोध पत्र के शीघ्र निष्पादन के लिए अनुसरण किया जाना चाहिए, तो अनुरोध पत्र भेजते समय उनका पालन किया जाएगा।

[फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2018.

G.S.R. 806(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of section 23 and sub-section (6) of section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Procedure for sending Letter of Request to the Contracting State for Service of Notice and Execution of Order of the Special Court) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Procedure for Sending Letter of Request to Contracting State) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "authorised officer" means an officer not below the rank of a Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules;

(b) "form" means the form appended to these rules;

(c) "Act" means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018);

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act.

3. **Manner of service of notice of the Special Court on fugitive economic offenders abroad through the letter of request**.—

(1) Where an application under section 4 of the Act has been duly filed, the Special Court shall issue a notice to an individual who is alleged to be a fugitive economic offender.

(2) The service of notice of the Special Court referred to in sub-rule (1) shall be made through a letter of request.

(3) The letter of request shall be in the Form appended to these rules.

(4) While finalising the letter of request, the Directorate of Enforcement established under section 36 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) shall ensure the compliance of all legal requirements.

(5) The authorised officer shall forward the letter of request in the Form in triplicate to the Ministry of Home Affairs.

(6) The nodal officer in the Ministry of Home Affairs shall ensure the timely transmission of the letter of request to the contracting State.

(7) The letter of request along with notice of the Special Court shall be forwarded to the authority concerned for effecting service in the contracting State.

(8) The service of notice in any mode under section 10 of the Act shall be treated as effective service by the Special Court.

4. **Manner of issuing letter of request to a Court or authority in the contracting State for execution of the order of the Special Court**.—

(1) The letter of request for execution of the order of the Special Court for confiscation of property in a Contracting State shall be in the Form appended to these rules.

(2) After issue of letter of request by the Special Court to the Court or the authority concerned in the contracting State for execution of its order, the authorised officer shall forward the same in triplicate to the Ministry of Home Affairs.

(3) The nodal officer in the Ministry of Home Affairs shall ensure the timely transmission of the letter of request to the contracting State.

FORM

[See sub-rule (3) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4]

Form of the Letter of Request

1. Details of the scheduled offence / brief facts

2. Reference of applicable sections of law (details not necessary)

3. Brief reference of reasons emerged from the enquiry which indicates that the requested fugitive economic offender is present in the contracting State and proceeds of crime or properties of the fugitive economic offender are situated in the contracting State.

4. Brief details of Assistance sought from the contracting State, that is, service of notice or execution of the order of the Special Court.

5. The basis of sending request, that is, provisions of Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (MLAT) between India and the contracting State/any other convention or treaty (Title of such convention/treaty to be given)/or on the basis of Assurance of Reciprocity.

Details in the letter of request

1. Correct official name of the Country
2. Contact Information/ Liaison Officer
3. Correct mention of either Treaty or Agreement (MLAT Countries)
4. Assurance of Reciprocity / Reciprocity Undertaking (Non-MLAT Countries)
5. Certified translation into official language
6. Letter of Request to be addressed to the correct Central Authority or the Court of the contracting State.
7. If any contracting State have other requirements and formats which must be followed for expeditious execution of the Letter of Request, that may be complied with while sending the Letter of Request.

[F. No. 6/3/2017-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)